

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2023—वैशाख 29, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 मार्च 2023

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 से 09 दिसम्बर 2022 तक (03 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 तथा 11 दिसम्बर, 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अप्रैल 2023

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2023 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-58/गृह-सी/परीक्षा/2023.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त-2023, दिनांक 01 अगस्त, 2023 से दिनांक 08 अगस्त 2023 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

मंगलवार, दिनांक 01-08-2023

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	प्रथम प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि. भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2.	प्रश्न पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
3.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
4.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
5.	प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	Paper-1, "Electrical Laws (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
मंगलवार, दिनांक 01-08-2023		
6.	द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया, दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	Paper-2, "Earthing and Electrical Safety (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 02-08-2023

(1)	(2)	(3)
9.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया “भाग-बी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
11.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया “भाग-सी” (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
12.	प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
61.	Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये.	
बुधवार, दिनांक 02-08-2023		
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व विभाग, भू-अभिलेख तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
62.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये.	

गुरुवार, दिनांक 03-08-2023

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए	
63.	Paper-5 “Switch gear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये.	
गुरुवार, दिनांक 03-08-2023		दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
26.	प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के), पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	Paper-6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 04-08-2023

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शुक्रवार, दिनांक 04-08-2023		
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सा.प्र.वि., भू-अभिलेख तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
शनिवार दिनांक 05-08-2023 एवं रविवार दिनांक 06-08-2023 को शासकीय अवकाश		
सोमवार, दिनांक 07-08-2023		
45.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
46.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	
सोमवार, दिनांक 07-08-2023		दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
51.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	प्रश्नपत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	तृतीय प्रश्न पत्र-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
मंगलवार, दिनांक 08-08-2023		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
58.	प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	

नोट :-

- सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.
4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-06-2023 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ-09-86/गृह-सी/परीक्षा/2022.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-12-2022 के द्वारा दिनांक 04-08-2022 को आयोजित विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2022 के प्रश्न पत्र “लेखा-प्रश्नपत्र-भाग-01 (बिना पुस्तकों के)” विषय में सम्मिलित उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची जारी की गई है. परीक्षा केन्द्र बिलासपुर के अंतर्गत सूची के सरल क्रमांक-42 में दर्शित सुश्री चंचल यादव, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, का नाम त्रुटिवश सुश्री अंचल यादव, अंकित है, जिसे एतद्वारा सुश्री चंचल यादव, पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 मार्च 2023

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15.1 में वर्णित तालिका में नवीन प्रविष्टि अनुक्रमांक-28 पर समावेश करते हुये नीति के परिशिष्ट-6.28 पर “छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2019” को समाविष्ट कर लागू करता है.

यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 मार्च, 2028 तक की कालावधि के लिए लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, 2023-28

राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करने, उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू करता है।

यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से पांच वर्ष अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2028 तक के लिए प्रभावशील होगी।

(1) प्रस्तावना (Introduction) :-

राज्य की कुल आबादी में से लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। किसी भी राष्ट्र/राज्य के आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त किए जाने के लिए पृथक से प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2023 को की गई घोषणा के संदर्भ में इस नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में मातृशक्ति की उद्यमिता सर्वविदित है। इसे रेखांकित किए जाने तथा समाज में इसके महत्व को अधिक स्वीकार्यता प्रदान किये जाने के लिए इस नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। वर्तमान में औद्योगिक/उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, अतः राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, उनकी कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग हो, इस हेतु राज्य शासन की ओर से आर्थिक प्रोत्साहन व समर्थन प्रदान किया जावे।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्टअप हेतु छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, 2023-28 लागू की जा रही है।

(2) उद्देश्य (Objective) :-

- 2.1 प्रचलित औद्योगिक नीति 2019-24 के उद्देश्य "महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण" का क्रियान्वयन किये जाने हेतु।
- 2.2 महिलाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का सृजन करना ताकि महिलायें स्वयं का उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ रोजगार प्रदाता की भूमिका भी निभा सकें।
- 2.3 राज्य की महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करना।
- 2.4 महिला श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करना।
- 2.5 कृषि संबंधी सहायक उद्योग/व्यवसाय, कुटीर उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना।

(3) रणनीति (Strategy) :-

- 3.1 इस नीति के अंतर्गत राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन इस नीति के माध्यम से दिये जायेंगे, जिसमें अनुदान, छूट एवं रियायतों के अतिरिक्त उद्यमिता में सुगमता के लिए राज्य के सभी विभागों में उद्यमिता के लिए शासकीय नियमों एवं प्रावधानों में आवश्यक निर्बाधन किया जायेगा।
- 3.2 राज्य के सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना की जावेगी, जहां राज्य में संचालित योजनाओं की जानकारी सुलभ करायी जायेगी।
- 3.3 विभाग के पोर्टल में महिला उद्यमिता से संबंधित सभी प्रोत्साहन प्रदान करने वाली जानकारी एक स्थान पर सिंगल विण्डो सिस्टम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। सिंगल विण्डो में प्रत्येक प्रकरण का पंजीकरण कर उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक आईडी) प्रदान किया जायेगा, जो कि प्रकरण के अनुसरण में संदर्भ हेतु प्रत्येक विभाग में उपयोग में लाया जायेगा। साथ ही प्रत्येक प्रकरण के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी, जो महिला उद्यमियों को जानकारी व सहायता प्रदान करेंगे।
- 3.4 नीति के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल विभाग होगा। नीति के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य स्तर पर उद्योग संचालनालय तथा जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जावेगा।
- 3.4 महिलाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जावेगा।
- 3.5 महिला द्वारा संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु प्रभावशाली तंत्र का विकास व अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जावेगा।

(4) पात्रता एवं क्रियान्वयन

- 4.1 राज्य में महिला उद्यमिता नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस नीति के अंतर्गत महिलाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र नवीन विनिर्माण/सेवा उद्यम की स्थापना, विद्यमान उद्यमों के विस्तार एवं शक्तीकरण में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन अर्थात् अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी। इस हेतु आवेदन के प्रारूप, प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रावधान औद्योगिक नीति 2019-24 के अधीन जारी अधिसूचनाओं में वर्णित अनुसार होंगे। इस नीति का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा इसके अधिनस्थ उद्योग संचालनालय, सीएसआईडीसी एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों एवं यथाआवश्यकता अन्य नामांकित एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा।

- 4.2 राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में उल्लेखित पात्र औद्योगिक/सेवा गतिविधियों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति, 2023-28 में वर्णित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं हेतु पात्र विनिर्माण उद्यम की सूची परिशिष्ट - 1 पर एवं सेवा/व्यवसाय उद्यम/गतिविधियों की सूची परिशिष्ट - 2 पर तथा इस नीति के अंतर्गत मंडी शुल्क छूट हेतु अपात्र उद्योगों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
- 4.3 औद्योगिक नीति 2019-24 के लिए अपात्र माने गए उद्योगों/सेवा उद्यमों तथा एल्कोहल, डिस्टिलरी आधारित ब्रेवरेजेस को इस नीति के अंतर्गत भी अपात्र माना जायेगा।

(5) परिभाषाएं एवं अन्य प्रावधान:-

- महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन/विस्तारीकरण/शवलीकरण हेतु पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत पात्रता हेतु "महिला उद्यमी" मान्य किये जाने हेतु निम्नांकित शर्त की पूर्ति आवश्यक होगी -
 - एकल स्वामित्व के प्रकरणों में महिला स्वामित्व।
 - भागीदारी फर्म होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत महिला भागीदारी।
 - भारतीय कंपनी अधिनियम/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनी होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत महिला अंशधारिता।
 - सहकारी संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत महिला सदस्य।
 - सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत गठित संस्था होने की स्थिति में न्यूनतम 51 प्रतिशत महिला सदस्य।
 - शत-प्रतिशत महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूह एवं एफपीओ।
- महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुरूप ही स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी, अर्थात् अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 70 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय श्रेणी में 40 प्रतिशत राज्य के निवासियों को संपूर्ण आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने की अवधि एवं इसके उपरान्त 5 वर्ष तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाना आवश्यक होगा तथा कुल रोजगार का न्यूनतम 60 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।
- महिला उद्यमियों द्वारा नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु भूमि/शेड-भवन किराये पर लिये जाने की स्थिति में किराये की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष (व्यवसाय उद्यम हेतु 05 वर्ष) का किराया अनुबंध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

4. इस नीति के संदर्भ में उक्त परिभाषित बिंदुओं को छोड़कर अन्य सभी परिभाषाएं यथा-आवश्यकता औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुरूप ही मान्य होंगी ।

(6) वित्तीय (ऋण) सहायता :-

- 6.1 महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र उद्यमों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अनुरूप वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के माध्यम से विभाग द्वारा वित्तीय सहायता (ऋण) उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस नीति के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता (ऋण) की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :-

1	विनिर्माण उद्यम	रु. 50.00 लाख
2	सेवा उद्यम	रु. 25.00 लाख
3	व्यवसाय उद्यम	रु. 10.00 लाख

(परियोजना लागत में भूमि की राशि, भूमि/दुकान का किराया सम्मिलित नहीं किया जायेगा। स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत भवन मद में प्रस्तावित परियोजना लागत राशि के अधिकतम 20 प्रतिशत तक की राशि मान्य की जा सकेगी।)

6.2 गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क की सहायता :-

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र उद्यमों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की सुगमता एवं सहजता हेतु राज्य शासन द्वारा सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत देय गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान किया जावेगा, जो ऋण स्वीकृति दिनांक से आगामी 5 वर्षों के लिए होगी।

- 6.3 इस नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर स्थापित होने वाले उद्यमों को अन्य आर्थिक निवेश प्रोत्साहन कंडिका (7) के अनुसार देय होगा।

(7) आर्थिक निवेश प्रोत्साहन :-(7.1) ब्याज अनुदान :-

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन/विस्तारीकरण/शवलीकृत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों के लिए प्राप्त किये गये सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा :-

उद्यम का स्तर	क्षेत्र क श्रेणी	सामान्य उद्यम			प्राथमिकता उद्यम			उच्च प्राथमिकता उद्यम		
		अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	अ	5	45	15	6	55	20	7	55	25
	ब	6	50	20	7	55	25	8	55	30
	स	7	60	30	8	65	35	9	65	40
	द	8	70	35	10	70	45	11	70	50
मध्यम उद्यम	अ	5	30	25	5	40	35	6	40	40
	ब	5	35	35	5	45	45	7	45	50
	स	7	55	45	8	60	55	9	60	55
	द	8	65	45	10	70	55	11	70	60

(7.2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन/विस्तारीकरण/शवलीकृत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान देय होगा -

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्यम		प्राथमिकता उद्यम		उच्च प्राथमिकता उद्यम	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि ₹ लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	अ	40	40	45	65	50	70
	ब	40	45	45	70	50	75
	स	40	65	45	85	50	95
	द	50	75	45	95	50	100
मध्यम उद्यम	अ	35	65	40	75	45	85
	ब	35	75	45	85	50	95
	स	40	85	50	110	50	115
	द	45	100	50	110	55	120

(टीप:- पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 7.2 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा बिंदु क्रमांक 7.3 अनुसार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। उक्त हेतु लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा।)

(7.3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :-

(केवल महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों हेतु)

क्षेत्र	सामान्य उद्यम	प्राथमिकता उद्यम	उच्च प्राथमिकता उद्यम
श्रेणी-अ	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी-ब	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत
श्रेणी-स	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 13 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 70 प्रतिशत
श्रेणी-द	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 13 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 16 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 110 प्रतिशत

टीप :- इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य संपूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षों में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट जीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा, जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी।

(7.4) विद्युत शुल्क छूट :-

महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को केवल पात्र नवीन उद्यम को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी:-

क्षेत्र	सामान्य उद्यम	प्राथमिकता उद्यम	उच्च प्राथमिकता उद्यम
श्रेणी-अ	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-ब	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-स	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-द	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 11 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

(7.5) स्टाम्प शुल्क से छूट -

महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी :-

- भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।
- ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

(7.6) मंडी शुल्क से छूट -

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण (केवल विनिर्माण) इकाइयों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/ इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट-3 में वर्णित अपात्र उद्यमों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि ₹ 2.50 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75% से अधिक नहीं होगी।

(7.7) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान –

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा श्रेणी के उद्यमों को उद्योग स्थापना हेतु तैयार कराये गये परियोजना प्रतिवेदन पर (उद्योग स्थापना उपरांत) किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम राशि ₹ 3.00 लाख।

(7.8) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा श्रेणी के उद्यमों को आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस. ओ. 22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, जेड (ZED) प्रमाणीकरण उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम ₹ 6.00 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रत्येक प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

(7.9) तकनीकी पेटेन्ट अनुदान –

महिला उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित एवं संचालित नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा श्रेणी के उद्यमों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 65 प्रतिशत राशि अधिकतम ₹ 12.00 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(7.10) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान –

महिलाओं द्वारा राज्य में स्थापित एवं संचालित नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों की श्रेणी में (संतृप्त श्रेणी के उद्यमों को छोड़कर) इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी. सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 65 प्रतिशत अधिकतम ₹ 12.00 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

(7.11) मार्जिन मनी अनुदान –

(अ) राज्य के महिलाओं द्वारा प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों में ₹ 5 करोड़ के पूंजीगत लागत की सीमा तक के नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 75.00 लाख तक होगी।

(ब) राज्य के महिलाओं द्वारा प्रस्तावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों में ₹ 2 करोड़ के पूंजीगत लागत की सीमा तक के नवीन सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 5.00 लाख तक होगी।

(7.12) दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान -

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नवीन एवं विद्यमान पात्र विनिर्माण/सेवा उद्यमों को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 55 प्रतिशत अनुदान की राशि की अनुदान प्रतिपूर्ति, 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रुपये 6.00 लाख वार्षिक की सीमा तक की जावेगी।

(7.13) इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)-

13.1 महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फूटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 30 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा।

13.2 महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्बन क्रेडिट के संबंध में दिये जाने वाले अनुदानों की प्राप्ति हेतु कंसलटेन्ट्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।

(7.14) परिवहन अनुदान -

नीति की अवधि में महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा राज्य में स्थापित इकाइयों में निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोड़कर निर्यात उन्मुख उद्यमों हेतु) के विपणन हेतु परिवहन पर किये गये वास्तविक व्यय (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा राशि रुपये 25 लाख प्रतिवर्ष, अधिकतम 07 वर्ष तक होगी। परिवहन व्यय की गणना निम्नानुसार होगी:-

- 1- निर्यात की स्थिति में - इकाइयों में निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए निर्माण स्थान से पोर्ट तक, परिवहन पर किये गये वास्तविक व्यय (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के अधिकतम मान्य सीमा तक अथवा वास्तविक व्यय, जो कम हो, सहायता प्रदान की जायेगी।
- 2- अंतरराज्यीय विक्रय की स्थिति में- इकाइयों में निर्मित उत्पादों का विक्रय राज्य के बाहर करने के लिए, निर्माण स्थान से उस राज्य के गंतव्य स्थान तक, परिवहन पर किये गये वास्तविक व्यय (शासकीय शुल्क एवं करों को छोड़कर) के अधिकतम मान्य सीमा तक अथवा वास्तविक व्यय, जो कम हो, सहायता प्रदान की जायेगी।

(7.15) औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/ रियायत -

नीति की अवधि में महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को उद्यम स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में आबंटित की जाने वाली भूमि पर भू-प्रब्याजी में निम्नानुसार छूट/रियायत प्रदान की जावेगी:-

विकासखण्डों की श्रेणी	सामान्य उद्यम	प्राथमिकता उद्यम	उच्च प्राथमिकता उद्यम
अ	10 प्रतिशत	40 प्रतिशत	50 प्रतिशत
ब	15 प्रतिशत	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत
स	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
द	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत	80 प्रतिशत

(7.16) ईपीएफ, ईएसआई अंशदान में छूट :-

महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआई में जमा अंशदान का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष तक होगी।

(7.17) किराया अनुदान :-

1. महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्टार्ट-अप इकाइयों को इन्क्यूबेशन दिनांक से 3 वर्ष तक इन्क्यूबेशन सेंटर में लिए जाने वाले शुल्क/किराया में 50 प्रतिशत तक, अधिकतम रुपये 96000/- वार्षिक अनुदान प्रदान की जायेगी।
2. महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्टार्ट-अप इकाइयों को उत्पादन/गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 3 वर्ष तक किराये के भवन में इकाई स्थापित करने की दशा में भुगतान किए गए मासिक किराये का 50 प्रतिशत, अधिकतम रुपये 96000/- वार्षिक अनुदान प्रदान किया जायेगा।

(7.18) उत्पाद पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग उन्नयन सहायता :-

महिलाओं द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके उद्यम में निर्माण किये जा रहे उत्पादों के आकर्षक पैकेजिंग के संबंध में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से लिये जाने वाले परामर्श हेतु देय शुल्क में 50 प्रतिशत तक, अधिकतम रुपये 75000/- वार्षिक अनुदान 5 वर्ष तक प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त के साथ ही इस नीति के अंतर्गत महिला उद्यमियों को उनके उत्पादों के बेहतर विपणन हेतु आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित पैकेजिंग, उत्पादों की एवं ब्रांडिंग हेतु करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के माध्यम से स्तर उन्नयन हेतु सलाह उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावेंगे।

(7.19) महिला स्व-सहायता समूहों को विशेष अनुदान :-

राज्य के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों महिला समूहों में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा इनके सशक्तिकरण को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला स्व-सहायता समूहों (SHG's) द्वारा स्थापित एवं संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यमों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में 01 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि प्रदान की जावेगी।

व्यवसाय के मामलों में राज्य शासन के अन्य विभागों से समन्वय कर ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायें एवं इस नीति के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे ऋणों के लिये ऋण की गारंटी एवं मार्जिन मनी सहायता हेतु प्रावधान किये जाने के प्रयास किये जायें।

(7.20) महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को विशेष सहायता :-

इस नीति के अंतर्गत महिलाओं द्वारा स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्टार्टअप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में एक वर्ष अतिरिक्त छूट की पात्रता होगी।

8. गैर वित्तीय सुविधाएं :-

- 8.1 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बी2बी चर्चाओं पर महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 8.2 महिला उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों में आवश्यकतानुसार कुशल एवं अकुशल रोजगार की मांग करने पर कौशल विकास केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 8.3 राज्य में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रदर्शनियों में महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्टअप के लिए 25 प्रतिशत स्टाल आरक्षित रखा जावेगा तथा स्टाल निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।
- 8.4 महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निविदा की प्रक्रिया में जमा करवाये जाने वाले EMD (Earnest Money Deposit) की राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी।
- 8.5 महिला उद्यमियों द्वारा पात्र सूक्ष्म, लघु उद्यम/सेवा उद्यम, ग्रामोद्योग/कुटीर उद्यम की स्थापना के संबंध में महिलाओं के प्रकरणों में 10,000 वर्गफुट तक के उद्यम स्थल संबंधी प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु की शर्त से छूट प्रदान किये जाने हेतु संबंधित नियमों में यथोचित संशोधन किया जायेगा।
- 8.6 महिला उद्यमियों को राज्य शासन द्वारा संचालित इन्क्यूबेशन सेंटर में आवश्यकतानुसार इन्क्यूबेशन की सुविधा प्रदान की जावेगी।

9. नीति का प्रशासकीय नियंत्रण -

- (अ) उपरोक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यथावश्यक अतिरिक्त प्रावधान समावेश/विलोपन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा।
- (ब) उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु सभी प्रकार के दिशा-निर्देश, क्रियान्वयन नियम, मार्गदर्शन आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

परिशिष्ट – 1

छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के अंतर्गतमान्य विनिर्माण गतिविधियों की सूची

1. चमड़े के उत्पाद
2. मोल्डिंग (इसमें कंघी, छाता, फ्रेम, प्लास्टिक के खिलौने आदि जैसे उत्पाद शामिल हैं)
3. प्राकृतिक सुगंध और स्वाद
4. ऊर्जा कुशल पंप
5. फर्नीचर और लकड़ी के उत्पाद
6. साइकिल के पुर्जे
7. रबर उत्पाद
8. ऑटो पार्ट्स कंपोनेंट्स- जिसमें हॉर्न बटन, डोर चौनल, वाइपर ब्लेड कंपोनेंट, बैटरी सेल टेस्टर शामिल हैं
9. कठोर धातु के बर्तन
10. ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उत्पाद
11. ट्रांसपोर्ट उपकरण को छोड़कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग- इसमें स्टील की अलमारी , कोंक और वॉल्व, वायर कटर आदि शामिल हैं
12. अभियांत्रिकी एवं निर्माण
13. चीनी मिट्टी और कांच के उत्पादों में छत की टाइलें, कांच के फर्श की टाइलें, ग्रेनाइट आदि शामिल हैं
14. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण
15. पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व
16. एक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री और आयुर्वेदिक उत्पाद
17. खादी उत्पाद और होजरी उत्पाद
18. कागज से बनी छपाई और अन्य उत्पाद
19. क्वायर उद्योग
20. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य गतिविधि।

नोट :-

केन्द्र एवं राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थी को इस नीति में उल्लेखित आर्थिक निवेश प्रोत्साहनों के लिये नियमानुसार पात्रता होगी। समान प्रकृति के अनुदान/छूट की मात्रा में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक अंतर की अनुदान/छूट हेतु पात्र होंगे।

परिशिष्ट - 2

**छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के अंतर्गत
मान्य सेवा/ व्यवसाय उद्यम गतिविधियों की सूची**

1. कम्प्यूटर/मोबाईल रिपेयरिंग सेंटर
2. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी/ आईटीईएस उत्पादों का व्यवसाय एवं सर्विसिंग सेंटर
3. झूलाघर
4. ब्यूटीपार्लर एवं स्पा सेवाएं
5. महिलाओं द्वारा संचालित रेस्टोरेट/टिफिन सर्विस, ढाबा एवं बेकरी हाउस
6. फोटो कॉपी सेंटर /साइबर कैफे/डेस्कटॉप सर्विसेस (Desktop Publishing & Printing Center)
7. लेडिस टेलरिंग शॉप एवं प्रशिक्षण संस्थान
8. कोचिंग इंस्टीट्यूट
9. महिलाओं द्वारा संचालित ई-रिक्षा
10. लॉन्ड्री एवं ड्रायक्लिनर्स सर्विसेस
11. बुटीक /सिलाई/कढ़ाई/हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र एवं सेवाएं
12. सेक्योरिटी गार्ड सर्विसेस
13. कॉल सेंटर
14. उद्योगों के लिए संचालित टेस्टिंग लैब
15. फोटो स्टूडियो एवं फिल्म एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर
16. केबल टी.वी. सर्विस प्रोवाइडर
17. ग्रामोद्योग एवं हैडीक्राफ्ट से संबंधित गतिविधियां जैसे स्पीनिंग, विविंग आदि
18. प्रिंटिंग प्रेस
19. प्लेसमेंट एवं मैनेजमेंट सर्विसेस
20. इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी
21. टेंट एवं केटरिंग सर्विसेस
22. महिलाओं के लिए संचालित जिम, योग केंद्र संबंधित गतिविधियां
23. संगीत/कला प्रशिक्षण केंद्र
24. कूरियर सर्विस
25. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण केंद्र
26. पैथालॉजी लैब
27. एडवरटाइजिंग एजेंसी
28. उपकरण रेंटल और लीजिंग
29. कृषि/फार्म उपकरण की सर्विसिंग यथा- ट्रैक्टर, पंप रिपेयरिंग, रिंग बोरिंग मशीन आदि सेवाएं
30. कम्प्यूटरीकृत डाटा से संबंधित बैक ऑफिस ऑपरेशन
31. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सुरक्षा
32. स्टेशनरी विक्रय
33. आईटी समाधान प्रदाता सेवाओं में एक सर्वर बैंक बनाना, एप्लिकेशन सेवा प्रदाता, स्मार्ट कार्ड अनुकूलन, सेवा प्रदाता आदि शामिल हैं
34. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य गतिविधि।

नोट :-

केन्द्र एवं राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने वाले लाभार्थी को इस नीति में उल्लेखित आर्थिक निवेश प्रोत्साहनों के लिये नियमानुसार पात्रता होगी। समान प्रकृति के अनुदान/छूट की मात्रा में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक अंतर की अनुदान/छूट हेतु पात्र होंगे।

परिशिष्ट – 3

**छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के अंतर्गत मंडी शुल्क से छूट हेतु
अपात्र उद्योगों की सूची**

1. राईस मिल
2. पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग
3. मुरमुरा
4. हालर मिल
5. पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
6. मिनरल वाटर
7. सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स
8. एल्कोहल ड्रिंक
9. भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम
10. राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट
11. खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई/रिफाईनरी)
12. ऐसे उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं

टीप:- अपात्र उद्योगों की उक्त सूची के सरल क्रमांक 1, 2, 3 (केवल मुरमुरा), 4, 10 एवं 11 में अंकित उद्योग राईस मिल, पैडी परबायलिंग एवं क्लिनिंग, मुरमुरा, हालर मिल, राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई/रिफाईनरी) को राज्य के औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 (स) व परिशिष्ट-7 (द) के लिए पात्र उद्योग माना जायेगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 4-17/2016/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (4) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :-

“(3) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).”

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 10 के कॉलम (4) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

“(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेषन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 4-17/2016/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-17/2016/18, दिनांक 17-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 17th April 2023

No. F 4-17/2016/18.—In exercise of the powers conferred by section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Services (Scale of Pay and Allowances) Rules, 1967, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

- For entry (3) of column (4) of serial number 8 of Schedule-III, the following entry shall be substituted namely:—
“(3) Certificate in Hindi or English typing 5000 (Key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).”
- For entry (3) of column (4) of serial number 10 of Schedule-III, the following entry shall be substituted, namely :—
“(3) One year diploma/certificate in data entry operator/programming from any recognized Institute and certificate of Hindi or English typing 5000 (Key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKK, Joint Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 मार्च 2023

क्रमांक एफ 07-11/2016/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 05-12-2017 द्वारा सारंगढ़ विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

सारंगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सारंगढ़	127, 130/1ख, 140/1, 2, 131/1, 143/1, 172/1/ख	2.633	कृषि व्यवसायिक, प्रस्तावित मार्ग	आवासीय (प्रस्तावित मार्ग छोड़ कर)

2. उक्त उपांतरण विकास योजना में त्रुटि सुधार हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अतः राज्य शासन एतद्वारा सारंगढ़ विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण सारंगढ़ विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिकी, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 7-15/2017/32.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री संजय शुक्ला, भारतीय वन सेवा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 21 एवं 22 सहपठित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 19 के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण नियुक्त करता है.

2. उपरोक्तानुसार नियुक्ति के फलस्वरूप श्री संजय शुक्ला की सेवा शर्तें, पदावधि, वेतन एवं भत्ते आदि ऊपर वर्णित अधिनियम/नियम के प्रावधानों से शासित होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र कुमार शुक्ला, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 1-14/2014/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-09-2015 द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 2006 आवंटन वर्ष के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को 09 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2015 को पूर्ण करने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3(2) (ii) के तहत दिनांक 01-01-2015 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड 15600-39100 ग्रेड पे रु. 7600/-) प्रदान किया गया है।

2. तत्समय श्री मयंक श्रीवास्तव (भापुसे-2006) के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित होने के कारण श्री श्रीवास्तव को उक्त वेतनमान प्रदाय नहीं किया गया है। श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच को समग्र विचारोपरांत विभागीय आदेश दिनांक 28-06-2022 द्वारा समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जा चुका है तथा उनके निलंबन अवधि दिनांक 28-05-2013 से 23-11-2013 तक को विभागीय आदेश दिनांक 28-02-2023 द्वारा पेंशन, सेवा काल की गणना इत्यादि व अन्य समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मान्य किया जा चुका है।

3. अतएव राज्य शासन एतद्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2006 आवंटन वर्ष के श्री मयंक श्रीवास्तव (भापुसे-2006) को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2015 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3(2) (ii) के तहत दिनांक 01-01-2015 से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड 15600-39100 ग्रेड पे रु. 7600/-) प्रदान किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिजीत सिंह, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 7-01/2020/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री तिलक राम कोशिमा, (भापुसे-2011), पुलिस अधीक्षक, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छ.ग. को दिनांक 10 अप्रैल 2023 से 21 अप्रैल 2023 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 07, 08, 09, 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिलक राम कोशिमा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश काल में श्री तिलक राम कोशिमा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिलक राम कोशिमा (भापुसे-2011) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

5. श्री तिलक राम कोशिमा, (भापुसे-2011), पुलिस अधीक्षक, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री त्रिलोक बंसल, (भापुसे-2016), पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 मार्च 2023

क्रमांक 15/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बेलगहना	जरगा प.ह.नं. 10	1.170	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य का डूबान क्षेत्र.

बिलासपुर, दिनांक 10 मार्च 2023

प्र. क्रमांक 19/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बेलगहना	खोगसरा प.ह.नं. 01	0.631	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	तुमाडबरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 मार्च 2023

प्र. क्रमांक 50/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोंडी प.ह.नं. 22	0.069	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सल्का व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्रमांक/227/202201031700029/अ-82/2021-22.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	कण्डोरा प.ह.नं. 14	0.133	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग (भ/स) जशपुर.	महुआटोली से लोधमा-जोकारी मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्रमांक/230/202201031700030/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	कुनकुरी	लोधमा	1.684	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग (भ/स) जशपुर.	महुआटोली से लोधमा-जोकारी मार्ग के निर्माण हेतु.
		प.ह.नं. 12 शासकीय भूमि	5.268		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवि मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक/637/भू-अर्जन/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	आवराभाठा प.ह.नं. 14	0.062	मण्डल रेल प्रबंधक वालतेरु मंडल पूर्व तट रेलवे डी.आरएम. ऑफिस कामप्लेक्स दोंडपति विशाखापटनम.	रेल्वे लाईन दोहरीकरण प्रयोजनार्थ.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनीत नंदनवार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 मार्च 2023

प्र. क्रमांक 10/अ-82/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-रतनपुर
(ग) नगर/ग्राम-छेरकाबांधा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.55 एकड़

खसरा नम्बर

रकबा
(एकड़ में)

(1)

(2)

80/1	0.04
82/1च	0.30
390/4	0.02
381/2	0.05
513/5	0.08
513/3	0.03
513/8	0.05
513/9	0.15
560	0.20
610/2	0.11
614/1	0.16
610/3	0.01
612/1	0.11
639/6	0.05
643/1	0.10
650	0.08
641	0.10
587/4	0.21
564/2	0.04
499/5	0.11

योग

51

5.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लारीपारा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.